

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार ।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 18 जून, 2007

विषय: जनपद हरिद्वार में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिये सिंचाई विभाग से किराये पर लिये गये भवनों के किराये के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1355/नाजिर सदर-2007-08, दिनांक 31.5.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायिक अधिकारियों के उपयोगार्थ सिंचाई विभाग के गणेशपुर आफिसर्स कॉलोनी, रुड़की में उपलब्ध कराये गये 08 आवासों के किराये के भुगतान किये जाने हेतु रुपये 30,000/- के प्रस्ताव के सापेक्ष किराये मद से सम्बन्धित धनराशि रु० 28140/- (अट्ठाईस हजार एक सौ चालीस रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- i) बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा शासन के अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।
- ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित कर जाय ।
- iii) निजी व्यक्तियों से किराये पर लिये गये भवनों के किराये का भुगतान नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के लिए अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-सिविल और सेशन न्यायाधीश-00-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

संख्या: 30-दो(1)/XXXVI(1)/2006-604/01-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, हरिद्वार ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार ।
4. वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
2018
(एम०एम०समवाल)
अनु सचिव ।